भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1044

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

सरकारी संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग में गिरावट

1044. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयो की रैंकिंग में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2024 के अनुसार एनआईआरएफ 2023 की तुलना में 20% से अधिक परिवर्तन हुआ है;
(ख) क्या आईआईएसईआर और आईआईटी जैसे सरकारी संस्थानों की तुलना में अधिक निजी विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों की रैंकिंग में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों/विश्वविद्यालयों की वार्षिक रैंकिंग (जिसे इंडिया रैंकिंग कहा जाता है) के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) शुरू किया गया था। इन रैंकिंग की कार्यप्रणाली पाँच व्यापक मापदंडों पर आधारित है जो "शिक्षण, अधिगम और संसाधन," "शोध और व्यावसायिक अभ्यास," "स्नातक परिणाम," "प्रसार और समावेशिता," और "सहकर्मी धारणा" हैं ।

एनआईआरएफ 2024 इंडिया रैंकिंग के अनुसार, "समग्र श्रेणी" में शीर्ष 100 में 82 संस्थानों ने वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में प्राप्त कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। यह एनआईआरएफ के मापदंडों पर उनके सुधार को दर्शाता है। इसके अलावा, 2024 इंडिया रैंकिंग में "समग्र श्रेणी" में शीर्ष 100 संस्थानों में से 36 सरकारी संस्थानों ने अपनी रैंक में सुधार किया है या उसे बरकरार रखा है, जबकि 24 निजी संस्थानों ने अपनी रैंक में सुधार किया है या उसे बरकरार रखा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। जबकि इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में कई पहलों को संस्थागत रूप दिया गया है, भारत सरकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को तीन घटकों अर्थात् "चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना", "विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढांचा अनुदान" और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए "बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)" के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) भी भारत रैंकिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है।

*****